

उत्थान और पतन

(Boom and Bust 2024)

2024

वैश्विक कोयला संयंत्र पाइपलाइन पर एक नज़र

ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, सीआरइए, इ3जी, रिक्लेम फाइनेंस, सिएरा क्लब, एसफओसी, किको नेटवर्क, बंगलदेश समूह, ट्रेड एशिया, एलायंस फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड क्लीन एनर्जी, चिली सस्टेनेबल, पोलेन ट्रांसिसिओनेस जस्टास, इनिसिएटिवा क्लिमैटिका डे मेक्सिको और अरयारा





वैश्विक कोयला संयंत्र पाइपलाइन पर एक नज़र (अप्रैल 2024)

[उत्थान और पतन 2024 \(Boom & Bust Coal 2024\)](#) में निम्नलिखित शीर्षक वाले खंड शामिल हैं

(1) कार्यकारी सारांश, (2) 2023 के प्रमुख विकास, (3) वैश्विक डेटा सारांश, (4) कोई नया कोयला नहीं: निर्माण में प्रवेश करने वाले अंतिम कोयला संयंत्र की दिशा में प्रगति, (5) चीन के बाहर नए निर्माण कार्य बीते नौ साल के सबसे निचले स्तर पर और चीन में आठ साल का उच्चतम स्तर, (6) चरणबद्ध सेवानिवृत्ति प्रगति, (7) 2023 में निजी वित्त कोयला नीति के रुझान, (8) चीन, (9) भारत, (10) ईयू27+यूके, (11) संयुक्त राज्य अमेरिका, (12) तुर्की, (13) इंडोनेशिया, (14) पाकिस्तान, (15) बांग्लादेश, (16) वियतनाम, (17) लाओस, (18) फिलीपींस, (19) दक्षिण कोरिया, (20) जापान, (21) ऑस्ट्रेलिया, (22) मध्य एशिया, (23) मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, (24) उप-सहारा अफ्रीका, (25) लैटिन अमेरिका, और (26) देश के अनुसार विकास और संचालन में कोयला बिजली क्षमता को सूचीबद्ध करने वाला एक परिशिष्ट।

इस अनुवाद में रिपोर्ट के केवल कुछ अंश शामिल हैं। [पूर्ण संस्करण ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर वेबसाइट पर अंग्रेजी में उपलब्ध है।](#)

ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के अलावा, रिपोर्ट के सह-लेखक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए), ई3जी, रिक्लेम फाइनेंस, सिएरा क्लब, एसएफओसी, किको नेटवर्क, बांग्लादेश गुप्स, ट्रेड एशिया, एलायंस फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड क्लीन एनर्जी, चिली सस्टेनेबल, पोलेन ट्रांसिसिओनेस जस्टिस, इनिसिएटिवा क्लिमाटिका डे मेक्सिको और अरयारा हैं।

कार्यकारी सारांश

2015 के पेरिस जलवायु समझौते के बाद से लगभग सभी देशों ने विकास के तहत अपने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की क्षमता को कम कर दिया है, और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों वाले आधे से अधिक देशों ने कोयला क्षमता को कम कर दिया है या कोयला आधारित परिचालन क्षमता को स्थिर रखा है। जलवायु संबंधी चिंताएं, प्रतिकूल अर्थशास्त्र और जनता के विरोध ने कई कोयला संयंत्र प्रस्तावों को रोका और कुछ कोयला संयंत्रों को वास्तविक रूप में बंद किया है। हालाँकि, आशाजनक गति के बावजूद, दुनिया की परिचालन कोयला बिजली क्षमता 2015 से 11% बढ़ गई है, और वैश्विक कोयला [उपयोग](#) और कोयला क्षमता 2023 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक कोयला क्षमता में 2023 में 48.4 गीगावाट (GW), या 2% की वृद्धि हुई है, जिससे कुल कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 2023 में 2,130 गीगावाट हो गई, इस कुल वृद्धि का दो-तिहाई हिस्सा सिर्फ चीन से आया है। चीन के बाहर भी इसमें 2019 के बाद पहली बार 4.7 गीगावाट की छोटी वृद्धि देखी गई है। हालांकि 2023 में नई सेवानिवृत्ति योजनाएं और चरणबद्ध सेवानिवृत्ति प्रतिबद्धताएं देखी गईं, लेकिन एक दशक से अधिक समय में किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में 2023 में सबसे कम कोयला क्षमता की सेवानिवृत्त हुई।

कोयला क्षमता में वृद्धि के प्रमुख संकेतकों में से एक - 'नए निर्माण की शुरुआत' में लगातार दूसरे वर्ष चीन के बाहर गिरावट आई है और यह 2015 में डेटा संग्रह शुरू होने के बाद से रिकॉर्ड वार्षिक निम्न स्तर पर पहुंच गई। चीन में, नए निर्माण के साथ, बिल्कुल विपरीत हुआ है, चीन में लगातार चौथे वर्ष नए निर्माण अंतर्गत कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि देखी गई है और यह आठ साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो कोयला परियोजनाओं को "सख्ती से नियंत्रित" करने की राष्ट्रपति शी की 2021 की प्रतिज्ञा के अनुरूप नहीं है। चीन के बाहर, 113 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता अभी भी विचाराधीन है, जो कि 2022 में 110 गीगावाट क्षमता से थोड़ा ही

अधिक है, इसका मुख्य कारण भारत में प्रस्तावों में वृद्धि है, इसके साथ-साथ चीन में, 268 गीगावॉट कोयला आधारित बिजली क्षमता विचाराधीन है, जो 2022 में 249 गीगावॉट से अधिक है। यह वैश्विक पूर्व-निर्माण क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि नए कोयला संयंत्रों के प्रस्तावों को रोकने और उनसे दूर जाने के आह्वान के महत्व को स्पष्ट करती है।

देशों को चरणबद्ध सेवानिवृत्ति प्रतिबद्धताओं को भी बढ़ाना चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि घोषणाओं को प्लांट-दर-प्लांट सेवानिवृत्ति योजनाओं में अनुवादित किया जाए। वर्तमान वैश्विक परिचालन कोयला क्षमता में से केवल 15% (317 गीगावॉट) क्षमता ही ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य के अनुरूप रिटायर होने के लिए प्रतिबद्ध है। 2040 तक कोयला बिजली के परिचालन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अगले 17 वर्षों तक प्रति वर्ष औसतन 126 गीगावॉट सेवानिवृत्ति की आवश्यकता होगी, जो प्रति सप्ताह लगभग दो कोयला संयंत्रों के बराबर है। निर्माणाधीन और पूर्व-निर्माण (578 गीगावॉट) कोयला संयंत्रों को अगर चालू किया गया तो कोयला क्षमता में और भी अधिक कटौती की आवश्यकता होगी और अधिक क्षमता की सेवानिवृत्ति की जरूरत होगी।

2023 के प्रमुख घटनाक्रम

- 2023 में परिचालन कोयला क्षमता में 2016 के बाद से सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से चीन में चालू किये जाने वाले नए कोयला संयंत्रों (47.4 गीगावॉट) में वृद्धि और संयुक्त राज्य अमेरिका (9.7 गीगावॉट) और यूरोप (5 गीगावॉट) में अन्य प्रमुख वर्षों की तुलना में कम सेवानिवृत्ति के कारण हुई है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग आधी परिचालन कोयला क्षमता को 2035 तक बंद करने या किसी अन्य ईंधन में परिवर्तित करने की योजना है। राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोयला उपयोग कम करने की गति में तेजी लाने की जरूरत है।
- यूरोपीय संघ 27 और यूनाइटेड किंगडम में, क्षेत्र की कोयला सेवानिवृत्ति योजनाएं और प्रतिबद्धताएं पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों की दिशा में आधे तक तो बढ़ रही हैं लेकिन उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षी बनाना जारी रखना चाहिए।
- 2023 में, बारह नए देशों ने पावरिंग पास्ट कोल अलायंस के सदस्य बनकर नो न्यू कोल के लिए (नई कोयला क्षमता न लगाने के लिए) प्रतिबद्धता जताई। एक सौ एक देशों ने या तो औपचारिक रूप से नो न्यू कोल के लिए प्रतिबद्धता जताई है या पिछले दशक में अपनी सभी कोयला योजना को छोड़ दिया है या बंद है।
- चीन और उसके बाद के दस देशों में वैश्विक पूर्व-निर्माण क्षमता का 95% हिस्सा है। शेष 5%, 21 देशों में विभाजित है, जिनमें से 11 के पास केवल एक परियोजना है और वे "नो न्यू कोल" का लक्ष्य हासिल करने की कगार पर हैं।
- 2023 में, चीन के बाहर प्रस्तावित कोयले की क्षमता की कमी को प्रभावित करके 20.9 गीगावॉट की बिल्कुल नई परियोजनाओं द्वारा उसकी दिशा बदल दी गई जिसका कारण भारत (11.4 गीगावॉट), कजाकिस्तान (4.6 गीगावॉट), और इंडोनेशिया (2.5 गीगावॉट) में प्रस्तावित नई क्षमता थी, इसके साथ-साथ 4.1 गीगावॉट की पहले से बंद की गई या रद्द की गई क्षमता को फिर से प्रस्तावित करने से भी काम हो रही प्रस्तावित क्षमता को भारी नुकसान हुआ।
- "कैप्टिव" कोयला बिजली परियोजनाएं, या परियोजनाएं जो ऊर्जा ग्रिड से बाहर हैं और औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती हैं, नए कोयला प्रस्तावों के लिए अंतिम आशा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, क्रोम स्मेल्टर के लिए निर्धारित दो परियोजनाएं जिम्बाब्वे की 2023 में प्रस्तावित 1.9 गीगावॉट नई कोयला क्षमता बनाती हैं। इंडोनेशिया में, निकल स्मेल्टर उद्योग को बिजली देने के लिए कोयला परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

- 2023 में, 23 शीर्ष निजी वित्तीय संस्थानों ने नई या नवीनतम कोयला नीतियों को अपनाया, जो 2022 में 57 संस्थानों द्वारा अपनाई गई नीतियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण मंदी है।
- सात प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह (G7) के पास दुनिया की परिचालन कोयला क्षमता का 15% (310 गीगावॉट) हिस्सा है। 2023 में जापान में नई इकाइयों के पूरा होने के साथ, G7 के पास अब निर्माण में कोई कोयला क्षमता नहीं है, लेकिन यहाँ अभी भी जापान में एक और अमेरिका में दो प्रस्ताव मौजूद हैं। प्रस्ताव कार्बन कैप्चर और अन्य "स्वच्छ कोयला" प्रौद्योगिकियों से जुड़े होने के कारण कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता से ध्यान हटाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले प्रभावी रूप से अनिश्चित और महंगे प्रयोग हैं।
- ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) दुनिया की 92% परिचालन कोयला क्षमता (1,968 गीगावॉट) और 88% (336 गीगावॉट) पूर्व-निर्माण कोयला क्षमता का घर है।
- भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा 11.4 गीगावॉट के पूरी तरह से नए कोयला प्रस्ताव पेश किए गए जोकि 2016 के बाद से किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक है, इसके साथ-साथ देश में कई लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाओं को भी पुनर्जीवित किया गया।
- ब्राज़ील की कुल पूर्व-निर्माण क्षमता में कमी देखी गई, लेकिन देश में अभी भी दो परियोजनाएँ शेष हैं, जोकि लैटिन अमेरिका की ऐसी अंतिम पूर्व-निर्माण क्षमता में से एक है।
- जबकि अधिकांश अन्य क्षेत्रों में नए प्रस्ताव इस तो स्थिर हैं या घट रहे हैं, मध्य एशिया में प्रस्तावित कोयला क्षमता क्षेत्र की वर्तमान परिचालन कोयला क्षमता के 45% के बराबर है और यह एक दशक पहले की प्रस्तावित क्षमता से दोगुनी से अधिक है।

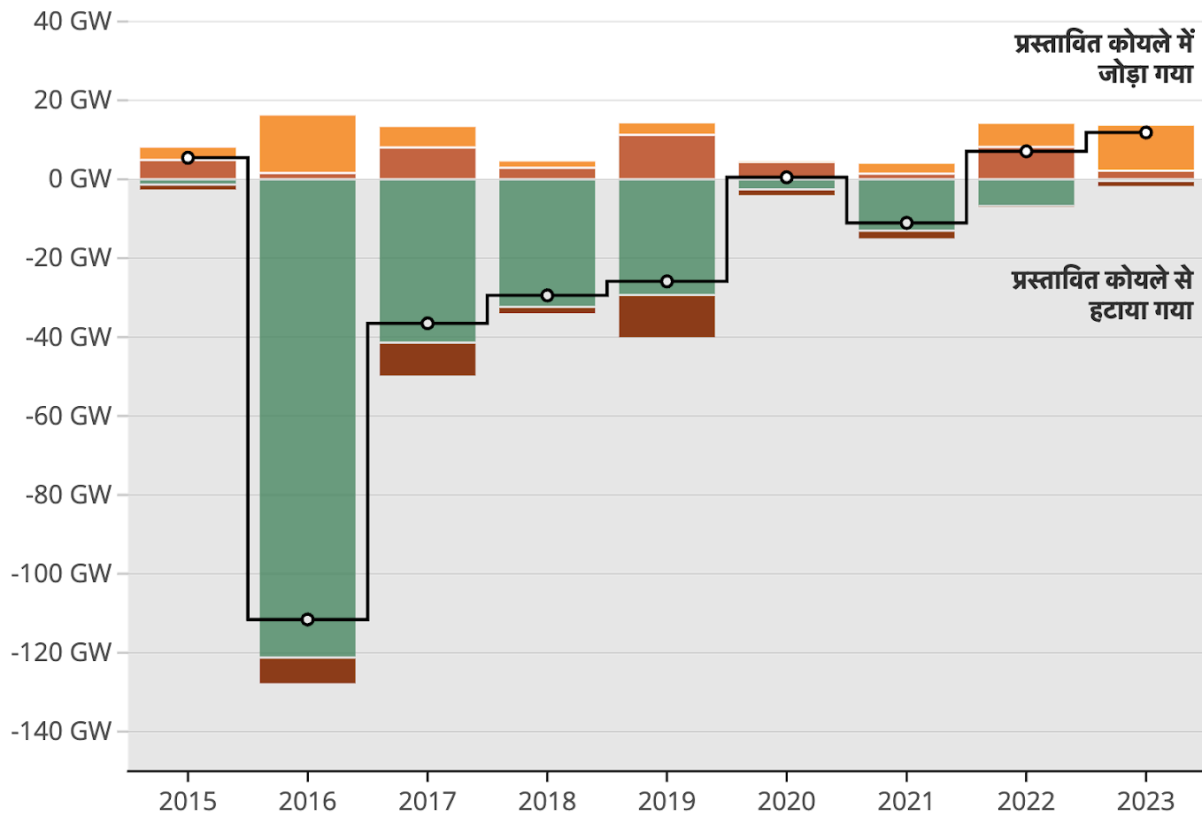
• • •

भारत

भारत में 2016 के बाद से नई कोयला परियोजनाओं की उच्चतम क्षमता देखी गई, और 2023 में लगभग कोई भी परियोजना रद्द या स्थगित नहीं की गई

भारत में प्रस्तावित कोयला आधारित बिजली क्षमता की स्थिति में बदलाव, गीगावाट (GW) में

■ शुद्ध परिवर्तन ■ रुकी हुई/स्थगित या रद्द की गई परियोजनाएँ ■ निर्माण शुरू ■ पुनः सक्रिय परियोजनाएं ■ विचाराधीन नई परियोजनाएं



स्रोत: ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर, जनवरी 2024

"रुकी हुई/स्थगित या रद्द की गई परियोजनाएँ" श्रेणी में केवल घोषित, पूर्व-अनुमति, या अनुमति प्राप्त स्थिति से रुकी हुई या रद्द की गई क्षमता में बदलाव को शामिल किया गया है, न कि रुकी हुई/स्थगित से रद्द की गई। यह "हटाई गई" क्षमता प्रस्तावित कोयले से दूर जाने की प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। हालाँकि, "निर्माण प्रारंभ" श्रेणी से हटाई गई क्षमता प्रगति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि यह कोयला क्षमता को संचालन के एक कदम करीब ले जाती है। निर्माण के लिए पुनः सक्रिय मानी जाने वाली क्षमता को प्रदर्शित नहीं किया गया है (2022 में 3.9 गीगावाट और 2023 में 1.2 गीगावाट)।



चित्र 24

भारत में दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कोयला आधारित क्षमता है, इसकी 237 गीगावाट परिचालन कोयला संयंत्र क्षमता दुनिया के परिचालन कोयले के दसवें हिस्से से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि 2022 के घटनाक्रम ने भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य में कोयला

आधारित बिजली क्षमता की भूमिका के संबंध में मिश्रित संकेत [दिए](#) थे, लेकिन कोयला संयंत्र प्रस्तावों में प्रगति के साथ-साथ 2023 में सरकारी निर्देशों से संकेत मिलता है कि भारत के कोयला क्षमता का कम से कम अगले कुछ वर्षों तक विस्तार जारी रह सकता है। दिसंबर 2023 में, बिजली मंत्री ने 2032 तक ग्रिड में लगभग 88 गीगावॉट नई थर्मल पावर प्लांट क्षमता जोड़ने की योजना की [घोषणा की](#), जिसमें से अधिकांश क्षमता कोयला आधारित होगी। केंद्र सरकार ने आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर कोयला बिजली विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है और निजी कंपनियाँ इस सम्बोधन पर ध्यान दे रही हैं और निजी क्षेत्र के बीते वर्षों कोयला आधारित क्षमता में निवेश की कमी के बाद अब निजी कंपनियाँ भारत में प्रस्तावित नई कोयला क्षमता के वित्तपोषण और निर्माण में रुचि [व्यक्त कर रही हैं](#)।

जबकि 2023 के मध्य में कुछ सुर्खियों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान [योजना की सराहना की गई थी](#), जिनके अनुसार भारत में नए कोयले की आपूर्ति को कम से कम अस्थायी रूप से "रोकने" का संकेत था, लेकिन उसी योजना में अनुमान लगाया गया था कि 2022-2027 के दौरान 25.58 गीगावॉट नई क्षमता चालू होने की संभावना है और सीके के साथ-साथ 2027-2032 की अवधि में फिर से लगभग उतनी ही (25.48 गीगावॉट) नई क्षमता के चालू होने की योजना बनाई गई है।

2022 में भारत की कोयला बिजली निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करने की शुरुआत के लिए एक आशाजनक वर्ष प्रतीत होने के बाद, 2023 में नए कोयला क्षमता के चालू होने और प्रस्तावित होने के साथ सेवानिवृत्ति योजना की कमी ने संकेत दिया कि कोयला बिजली क्षमता को कम करने की अभी कोई संभावना नहीं है। 2023 में भारत ने 5.5 गीगावॉट नई कोयला क्षमता चालू की, जो 2022 में चालू की गई क्षमता (2.0 गीगावॉट) से दोगुनी से भी अधिक है। नई कमीशन की गई क्षमता में से 1.8 गीगावॉट निजी स्वामित्व में है और शेष 3.7 गीगावॉट या तो सरकारी उद्यमों के सीधे स्वामित्व में है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), राज्य उद्यमों या दोनों के बीच संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उनके स्वामित्व में है।

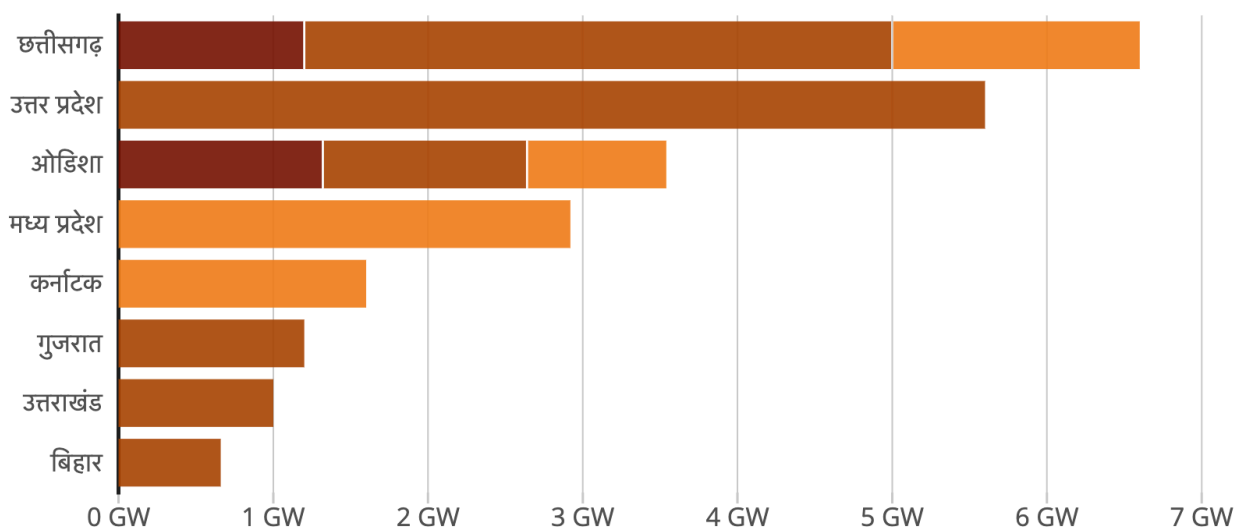
2023 में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र ने भारत में 11.4 गीगावॉट के पूरी तरह से नए कोयला प्रस्ताव पेश किए, जो 2016 के बाद से किसी भी वर्ष में नई प्रस्तावित क्षमता से अधिक है (चित्र 24)। हालाँकि इस नई क्षमता का तीन-चौथाई (8.6 GW) केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा समर्थित है, लेकिन एस्सार और अदानी पावर जैसी निजी संस्थाओं ने भी 1.2 GW [काजुरदा पावर स्टेशन](#) और 1.6 GW [रायखेडा विस्तार का प्रस्ताव रखा है](#)।

2023 में कोयला परियोजनाओं को अनुमति प्राप्त और पूर्व-अनुमति मंजूरी देने में वृद्धि देखी गई और इसके साथ ही लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाओं के पुनः शुरु होने में भी वृद्धि देखी गई। 2023 में, छह बिजली स्टेशनों में दस कोयला आधारित इकाइयों को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई, जो वर्ष के लिए नई स्वीकृत कोयला क्षमता की कुल 7.3 गीगावॉट थी। इससे भी अधिक 2023 में संदर्भ की शर्तें (ToR) प्राप्त करने वाले 12 विभिन्न संयंत्रों में 15.2 गीगावॉट क्षमता के साथ कोयला संयंत्र प्रस्ताव अनुमति प्रक्रिया में आगे बढ़े। 2023 में 2.2 गीगावॉट की रुकी हुई/स्थगित क्षमता को भी अनुमति प्रक्रिया में पुनः सक्रिय किया गया, जोकि पूर्ण रूप से निजी स्वामित्व में थी। अगले चार वर्षों के भीतर कोयला उत्पादन को [दोगुना करने](#) की सरकार की प्रतिज्ञा के साथ ये घटनाक्रम यह स्पष्ट करते हैं कि, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में हालिया प्रगति के बावजूद, देश का कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने या बाहर करने का कोई इरादा नहीं है।

भारत में आठ राज्यों ने 2023 में नई प्रस्तावित कोयला परियोजनाओं को शुरू किया, पुनः सक्रिय किया या अनुमति दी

2023 में भारत की प्रस्तावित कोयला क्षमता में राज्य के अनुसार स्थिति परिवर्तन, गीगावाट (GW) में

■ निर्माण प्रारंभ/पुनः प्रारंभ ■ नया प्रोजेक्ट प्रारंभ/पुनः सक्रिय हुआ ■ नव अनुमति



स्रोत: ग्लोबल कोल प्लान्ट ट्रैकर, जनवरी 2024



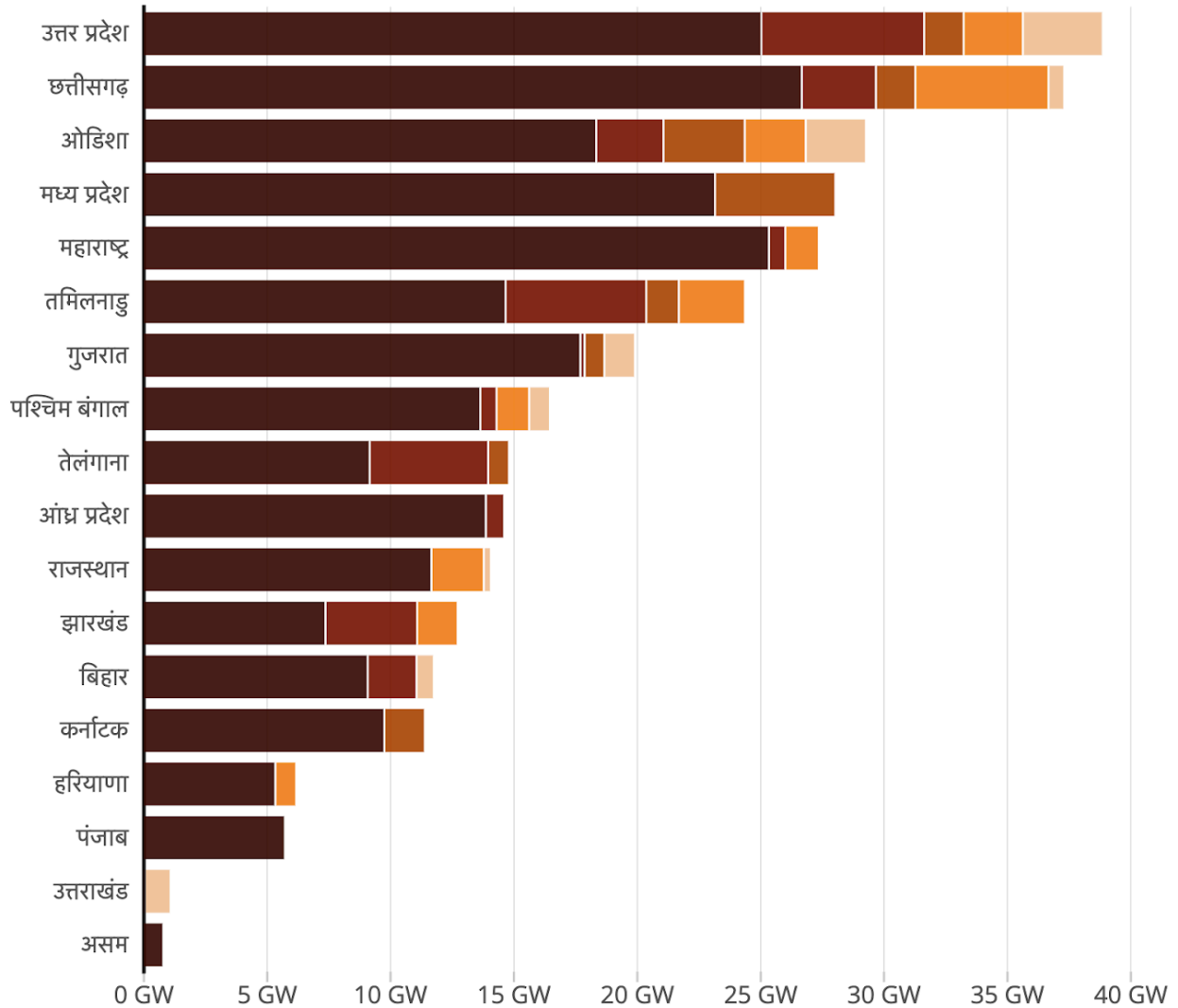
चित्र 25

छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों में भारत में सबसे बड़ी परिचालन कोयला क्षमता है, और वर्तमान में 2023 में क्रमशः 6.6 गीगावाट और 5.6 गीगावाट प्रस्तावित क्षमता के साथ देश में कोयला क्षमता के विस्तार का नेतृत्व कर रहे हैं (चित्र 25)। छत्तीसगढ़ वर्तमान में सबसे अधिक परिचालन कोयला क्षमता (26.7 गीगावाट) वाला राज्य है, लेकिन यदि दोनों राज्यों में वर्तमान में प्रस्तावित और निर्माणाधीन क्षमता का निर्माण हो जाए तो उत्तर प्रदेश जल्द ही आगे निकल सकता है (चित्र 26)।

यदि सभी प्रस्तावित क्षमता का निर्माण किया जाता है तो उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष कोयला-जलाने वाला राज्य बन सकता है

स्थिति के अनुसार भारतीय राज्यों में कोयला आधारित बिजली क्षमता, गीगावाट (GW) में

■ चालू ■ निर्माणाधीन ■ अनुमति प्राप्त ■ पूर्व-अनुमति ■ घोषित



स्रोत: ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर, जनवरी 2024



चित्र 26

पूरे 2023 के दौरान, पहले से सीमित क्षमता की केवल [0.2 गीगावाट क्षमता ही](#) औपचारिक रूप से बंद की गई, यह वार्षिक सेवानिवृत्ति के लिए आठ साल का सबसे निचला स्तर था। बढ़ती मांग और विभिन्न सरकारी संकेतों, जिसमें जनवरी 2023 में सीईए के सभी कंपनियों

को 2030 तक किसी भी थर्मल पावर क्षमता को रिटायर न करने की [सलाह दी गई है](#) को देखते हुए यह रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है।

[तालचेर पावर स्टेशन \(स्टेज III\)](#) में दो नई इकाइयों का निर्माण शुरू हुआ, जिससे एनटीपीसी की वर्तमान में निर्माणाधीन क्षमता लगभग [10 गीगावॉट हो गयी है](#)। पहले से ही निर्माणाधीन क्षमता के अलावा, एनटीपीसी ने फरवरी 2024 में आगामी वर्षों में 16 गीगावॉट कोयला आधारित क्षमता बनाने का [वादा किया](#)।

2023 में [एथेना छत्तीसगढ़ पावर स्टेशन पर निर्माण फिर से शुरू होता दिखाई दिया](#), इसका विकास लंबे समय से रुका हुआ था और पहले रद्द माना गया था। पर्यावरणीय अनुमति के मुद्दों के वर्षों के बाद भारत के राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के तहत दिवालिया कार्यवाही के बाद, एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड को 2022 में प्रमुख खनन कंपनी वेदांत द्वारा अधिग्रहित किया गया था और आखिरकार नए सिरे से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के बाद 2023 के अंत में निर्माण जारी किया गया। इसी तरह, [मीनाक्षी एनर्जी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को](#) एनसीएलटी परिसमापन कार्यवाही के माध्यम से वेदांता द्वारा अधिग्रहित किया गया था, और इसके फिर से शुरू किए गए निर्माण से 2024 में नई इकाइयों के संचालन के लिए तैयार होने की उम्मीद थी। IIEFA के अनुसार, भारत में ऐसी फंसी हुई संपत्तियों का [अधिग्रहण और पुनरुद्धार](#) निवेश नई जीवाश्म-ईंधन-आधारित क्षमता का एक लाभकारी विकल्प हो सकता है, विशेष रूप से जब नए परियोजना मालिक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इकाइयों के पुनः उपयोग की सुविधा से पहले केवल तब तक कोयले का उपयोग करने के लिए "अधिग्रहण-सेवानिवृत्ति-पुनर्उद्देश्य" रणनीति अपनाते हैं, जब तक कि अल्पकालिक ऊर्जा मांगों की उपयोग आवश्यकता होती है।

2023 में CEA द्वारा कई अन्य लंबे समय से रुकी हुई/स्थगित या फंसी हुई परियोजनाओं को 2023 और 2031 के बीच "पुनर्जीवित होने की संभावना" के रूप में चिह्नित किया गया था। दोनों झारसुगुड़ा [इंडस्ट्रीज-बाराथ](#) और [मालीब्राह्मणी](#) बिजली स्टेशनों को एनसीएलटी परिसमापन के तहत नए अधिग्रहण के बाद 2023 में संदर्भ की नई शर्तें (ToR) प्राप्त हुईं और इसके बाद दोनों परियोजनाओं पर रुके हुए निर्माण को पूरा करके 2024-2025 में पूरा करने की उम्मीद थी। लैंको [अमरकंटक संयंत्र](#), जिसकी तीसरी और चौथी इकाई मालिक की चल रही कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CRIP) के कारण 2016 से "रुका हुआ निर्माण कार्य" स्थिति पर थी, ये इकाइयाँ 2023 और 2024 की शुरुआत में भारतीय ऊर्जा दिग्गज अदानी और जिंदल के बीच तनावग्रस्त बिजली परियोजनाओं को हासिल करने के लिए बोली युद्ध में प्रतिस्पर्धा के कारण पुनरुद्धार के दौर से गुजर रही थी। [बिजोरा](#), [बिंजकोटे](#) और [गोर्गी बिजली स्टेशनों को](#) भी उनके मालिकों या CEA द्वारा आने वाले वर्षों में पुनरुद्धार के लिए 2023 में तैयारी करने का संकेत दिया गया था।

3.4 गीगावॉट रुकी हुई क्षमता के अलावा, जिसे 2023 में पहले ही पुनर्जीवित कर दिया गया था, भारत के बिजली मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों से देश के दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत NCLT प्रक्रियाओं के माध्यम से तनावग्रस्त और फंसे हुए बिजली परिसंपत्तियों को प्राप्त करके उनका लाभ उठाने का [आग्रह](#) किया है। इस नीति को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक और निजी बिजली कंपनियां उन कोयला परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए निवेश जारी रख सकती हैं जिन्हें लंबे समय से बंद या रद्द माना गया है।

साथ ही, देश को कोयले के बिगड़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2015 में कोयला संयंत्रों के लिए अधिक कठोर प्रदूषण मानक पेश किए, लेकिन मानकों के अनुपालन की समय सीमा को बार-बार नजरअंदाज किया गया और [पीछे धकेल दिया गया](#)। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक व्यवस्थित कदम जलवायु संकट का सामना करने, आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, नौकरियां पैदा करने और पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में मदद करेगा। एक साथ कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों में निवेश करने से भारत के लिए ऊर्जा परिवर्तन और भी खराब हो जाएगा।